

Identification of Challenges in the Implementation of National Education Policy 2020

¹**Dr. Pallavi Aadhav**

Research Scholar, Department of Education
Oriental University, Indore, Madhya Pradesh

²**Prof. Dr. Geetanjali Sharma**

Professor and Dean, Department of Education
Oriental University, Indore, Madhya Pradesh

Abstract

The National Education Policy 2020 is a visionary initiative aimed at bringing comprehensive and structural transformation to the Indian education system. Its primary objective is to make education more inclusive, flexible, multidisciplinary, and skill-oriented. The policy emphasizes the holistic development of learners, promotion of critical thinking, creativity, and life-oriented learning. However, the actual success of any education policy depends on its effective and practical implementation, and this is the area where several challenges tend to emerge. The main objective of the present study is to identify the major challenges faced in the implementation of the National Education Policy 2020. To achieve this objective, descriptive and analytical research methods were employed. Data were collected from selected secondary and higher secondary schools in Indore district of Madhya Pradesh. A total of 200 respondents participated in the study, including 120 teachers, 40 principals, and 40 members of school management committees. A self-constructed Likert-type questionnaire was used as the data collection tool, and its reliability was ensured using Cronbach's Alpha (0.82). Statistical analysis involved the use of mean, standard deviation, and t-test techniques. Based on the analysis, it was concluded that major challenges in the implementation of the National Education Policy 2020 include lack of teacher training, shortage of resources, digital divide, lack of administrative coordination, and socio-regional inequalities. In particular, it was found that inadequate teacher preparedness and lack of technical competence create significant barriers to effective policy implementation, while unequal access to digital resources further increases educational disparities. Therefore, it can be concluded that although the National Education Policy 2020 is highly progressive and transformative in nature, its successful implementation requires multi-level corrective measures. The present study provides useful suggestions for policymakers, educators, and administrators, which may contribute to making the education system more effective, inclusive, and quality-oriented.

Keywords: National Education Policy 2020, Policy Implementation, Educational Challenges, Teacher Training, Digital Divide, Educational Infrastructure

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान

1. डॉ. पल्लवी आढाव

शोधार्थी, शिक्षा विभाग

ओरिएंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

2. प्रो. डॉ. गीतांजलि शर्मा

प्रोफेसर एवं डीन, शिक्षा विभाग,

ओरिएंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयी तथा कौशल-आधारित बनाना है। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता तथा जीवनोपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। तथापि, किसी भी शिक्षा नीति की वास्तविक सफलता उसके प्रभावी एवं व्यवहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, और यही वह क्षेत्र है जहाँ अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उभरकर सामने आती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया तथा मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले के चयनित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कुल 200 उत्तरदाताओं (120 शिक्षक, 40 प्रधानाचार्य एवं 40 विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य) से आंकड़े संकलित किए गए। आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित लिफ्ट प्रकार प्रश्नावली का

प्रयोग किया गया, जिसकी विश्वसनीयता क्रोनबाख अल्फा (0.82) द्वारा सुनिश्चित की गई।

सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत माध्य, मानक विचलन एवं t -परीक्षण का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों का अभाव, डिजिटल विभाजन, प्रशासनिक समन्वय की कमी तथा सामाजिक-क्षेत्रीय असमानताएँ प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान हैं। विशेष रूप से यह पाया गया कि शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी एवं तकनीकी दक्षता का अभाव नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, जबकि डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता शिक्षा में असंतुलन को बढ़ाती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने स्वरूप में अत्यंत प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी है, किन्तु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए बहुस्तरीय सुधारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है, जो शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा का क्रियान्वयन, शैक्षिक चुनौतियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल विभाजन, शैक्षिक अधोसंरचना, प्रशासनिक समन्वय, समावेशी शिक्षा, शिक्षा में असमानता, नीति विश्लेषण

1. प्रस्तावना

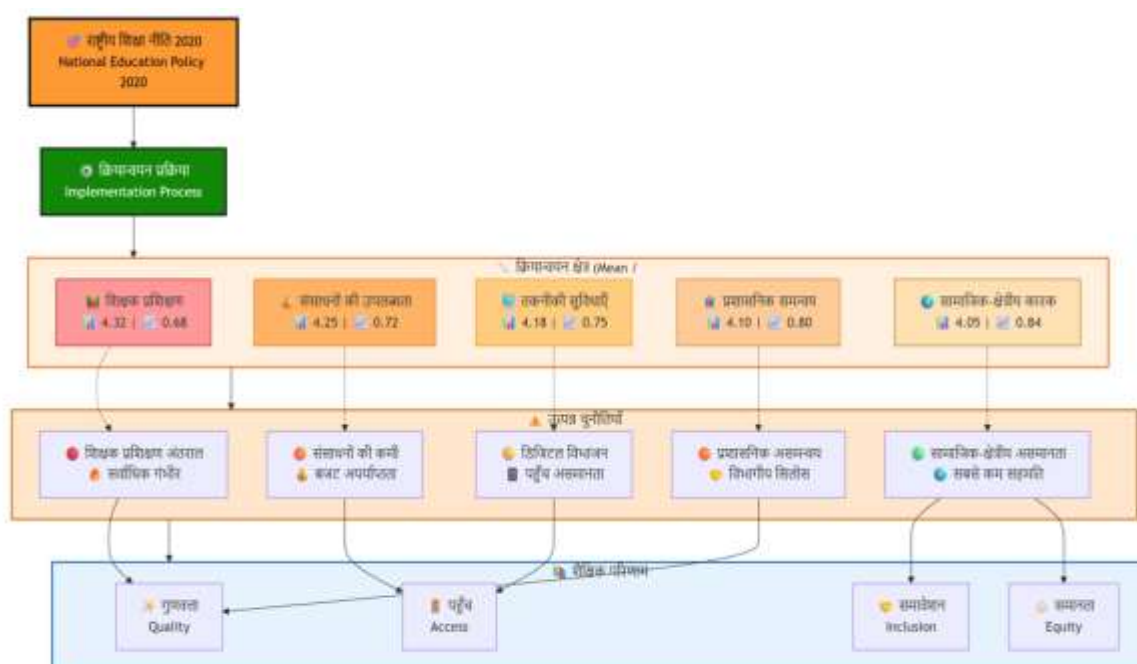
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक एवं संरचनात्मक सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रखते हुए उसे कौशल-आधारित, अनुभवात्मक एवं जीवनोपयोगी बनाने पर बल देती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, वहाँ शिक्षा प्रणाली को समयानुकूल परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया, जो लगभग तीन दशकों के पश्चात् भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक व्यापक सुधारात्मक कदम के रूप में सामने आई है।

यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, समानतापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 की नवीन शैक्षिक संरचना, बहुभाषिकता का प्रोत्साहन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का एकीकरण, कौशल विकास, डिजिटल अधिगम तथा बहुविषयी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयामों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही यह नीति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास पर विशेष बल देती है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन सकें।

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने उद्देश्यों एवं प्रावधानों की दृष्टि से अत्यंत प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक असमानताएँ विद्यमान हैं, वहाँ किसी भी नीति का समान रूप से कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया बन जाता है। संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, डिजिटल विभाजन, प्रशासनिक समन्वय की कमी तथा सामाजिक-क्षेत्रीय

असमानताएँ इस नीति के क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाओं के रूप में उभरती हैं।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उन चुनौतियों की पहचान की जाए, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिससे नीति के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सके।



चित्र 1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का संकल्पनात्मक ढाँचा

2. साहित्य समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न अध्ययनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नीति अपने स्वरूप में अत्यंत व्यापक एवं परिवर्तनकारी है, किन्तु इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (2020) द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को समावेशी, बहुविषयी एवं कौशल-आधारित बनाने पर बल दिया गया है। नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला एवं अधिगम-केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है, किन्तु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संसाधनों, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

तिलक (2021) के अनुसार, भारत में शैक्षिक सुधारों के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक प्रमुख निर्धारक होती है। यदि शिक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता, तो नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति सीमित रह जाती है। इसी संदर्भ में आज़ाद एवं गुप्ता (2022) ने यह इंगित किया कि शिक्षा प्रणाली में अधोसंरचना की असमानता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।

जेना (2020) ने अपने अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में वर्णित करते हुए यह बताया कि नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक नई शिक्षण विधियों एवं तकनीकी साधनों के उपयोग में दक्ष नहीं होंगे, तो नीति के उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाएगा।

कुमार (2021) के अनुसार, डिजिटल शिक्षा के विस्तार के बावजूद डिजिटल विभाजन एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण शिक्षा में असंतुलन उत्पन्न होता है, जो नीति के समावेशी दृष्टिकोण के विपरीत है।

यूनेस्को (2021) की रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए केवल उपकरणों की उपलब्धता ही पर्याप्त

नहीं है, बल्कि शिक्षकों की तकनीकी दक्षता एवं विद्यार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

विश्व बैंक (2022) के अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक संरचना एवं निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है। यदि विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं होता, तो नीति के परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाते।

उपरोक्त अध्ययनों के समेकित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ बहुआयामी एवं परस्पर संबंधित हैं। ये चुनौतियाँ केवल संसाधनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधाओं, प्रशासनिक समन्वय एवं सामाजिक असमानताओं से भी जुड़ी हुई हैं।

साथ ही यह भी देखा गया है कि अधिकांश अध्ययन नीति के विभिन्न आयामों पर पृथक-पृथक रूप से केंद्रित हैं, जबकि इन सभी चुनौतियों का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन इन सभी पहलुओं को एकीकृत दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, जिससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक एवं ठोस सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

3. उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने हेतु एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक शोध पद्धति का अनुसरण किया गया है। इस शोध पद्धति के अंतर्गत अध्ययन

के स्वरूप, विधि, जनसंख्या, प्रतिदर्श, उपकरण, डेटा संकलन प्रक्रिया तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की विधियों को क्रमबद्ध रूप में निर्धारित किया गया है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक बन सकें।

4.1 शोध का स्वरूप

प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है।

- वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है।
- विश्लेषणात्मक शोध के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों के कारणों एवं प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया है।

यह स्वरूप अध्ययन को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

4.2 शोध विधि

इस शोध में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है, क्योंकि यह विधि उत्तरदाताओं के विचारों, अनुभवों एवं दृष्टिकोणों को समझने के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों—शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंधन समिति—से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त की गई।

4.3 अध्ययन की जनसंख्या

प्रस्तुत शोध की जनसंख्या मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित हितधारकों को सम्मिलित करती है।

इसमें शामिल हैं-

- शिक्षक

- प्रधानाचार्य
- विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य

यह जनसंख्या अध्ययन के विषय के अनुरूप उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक मानी गई है।

4.4 प्रतिदर्श

शोध में कुल 200 उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

घटक	संख्या
शिक्षक	120
प्रधानाचार्य	40
वीएमसी सदस्य	40
कुल	200

यह प्रतिदर्श विभिन्न स्तरों के संतुलित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है।

4.5 प्रतिदर्श चयन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन विधि का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं तथा जिनके पास इस प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारिक अनुभव उपलब्ध है। इस विधि के माध्यम से शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों जैसे प्रमुख हितधारकों को सम्मिलित किया गया, जिससे अध्ययन को यथार्थ एवं बहुआयामी दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। अतः यह प्रतिदर्श चयन

विधि अध्ययन की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता एवं निष्कर्षों की प्रामाणिकता को सुदृढ़ बनाती है।

4.6 शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है, जो लिफ्ट प्रकार के पाँच-बिंदु मापक पर आधारित है। इस प्रश्नावली में कुल 25 कथनों को सम्मिलित किया गया है, जिनके माध्यम से उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण, अनुभव एवं धारणा का आकलन किया गया। प्रत्येक कथन के लिए पाँच विकल्प—पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत—प्रदान किए गए, जिससे उत्तरदाताओं को अपनी सहमति या असहमति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार यह उपकरण शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को मापने के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी पाया गया।

4.7 वैधता एवं विश्वसनीयता

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त प्रश्नावली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु इसे विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रत्येक कथन की प्रासंगिकता, स्पष्टता एवं शोध के उद्देश्यों के अनुरूपता का परीक्षण कर आवश्यक संशोधन सुझाए, जिसके आधार पर प्रश्नावली को अंतिम रूप प्रदान किया गया। विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए क्रोनबाख अल्फा गुणांक का उपयोग किया गया, जिसका मान 0.82 प्राप्त हुआ, जो उच्च स्तर की आंतरिक संगति को दर्शाता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रयुक्त शोध उपकरण न केवल वैध है, बल्कि पर्याप्त रूप से विश्वसनीय भी है।

4.8 डेटा संकलन की प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का संकलन एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम चयनित विद्यालयों की सूची तैयार की गई तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई। इसके पश्चात् शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उत्तरदाताओं का चयन किया गया और उन्हें स्वनिर्मित प्रश्नावली वितरित की गई। उत्तरदाताओं को प्रश्नावली भरने की विधि एवं उत्तर देने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाई गई, जिससे वे अपने विचारों को सही रूप में अभिव्यक्त कर सकें। तत्पश्चात् भरी हुई प्रश्नावलियों को एकत्रित किया गया तथा अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण प्रश्नावलियों को पृथक कर दिया गया। अंततः उपयुक्त एवं पूर्ण प्रश्नावलियों से प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित कर विश्लेषण हेतु तैयार किया गया। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उत्तरदाताओं की गोपनीयता एवं नैतिक मानकों का पूर्णतः पालन किया गया।

4.9 स्कोरिंग पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में प्रश्नावली के उत्तरों को परिमाणात्मक रूप देने हेतु एक व्यवस्थित स्कोरिंग पद्धति अपनाई गई, जिसमें सकारात्मक कथनों के लिए पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्णतः असहमत विकल्पों को क्रमशः 5, 4, 3, 2 एवं 1 अंक प्रदान किए गए, जबकि नकारात्मक कथनों के लिए इस क्रम को उलटते हुए 1, 2, 3, 4 एवं 5 अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार प्रत्येक उत्तरदाता का कुल स्कोर निर्धारित किया गया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च स्कोर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अधिक चुनौतियों की ओर संकेत करता है, जबकि निम्न स्कोर अपेक्षाकृत कम चुनौतियों को दर्शाता है।

4.10 सांख्यिकीय विश्लेषण की विधि

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया, जिनमें मुख्य रूप से माध्य, मानक विचलन तथा t -परीक्षण सम्मिलित हैं। माध्य के माध्यम से

उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का औसत स्तर ज्ञात किया गया, जबकि मानक विचलन द्वारा आंकड़ों के प्रसरण एवं विविधता का आकलन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न समूहों के मध्य अंतर की जांच के लिए t -परीक्षण का प्रयोग किया गया। इन सभी सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से प्राप्त परिणामों का तार्किक, वैज्ञानिक एवं उद्देश्यपरक विश्लेषण किया गया, जिससे अध्ययन के निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आंकड़ों का विश्लेषण माध्य एवं मानक विचलन के माध्यम से किया गया, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ प्रमुख रूप से विद्यमान हैं।

तालिका 5.1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ (माध्य एवं मानक विचलन)

क्रमांक	चुनौती का प्रकार	माध्य	मानक विचलन
1	शिक्षक प्रशिक्षण की कमी	4.32	0.68
2	संसाधनों का अभाव	4.25	0.72
3	डिजिटल विभाजन	4.18	0.75
4	प्रशासनिक समन्वय की कमी	4.1	0.8
5	सामाजिक-क्षेत्रीय असमानता	4.05	0.84

व्याख्या

उपरोक्त तालिका 5.1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उच्च स्तर पर विद्यमान हैं, क्योंकि सभी कथनों का माध्य मान 4.00 से अधिक पाया गया है, जो यह

संकेत करता है कि उत्तरदाताओं द्वारा इन समस्याओं के प्रति उच्च सहमति व्यक्त की गई है।

तालिका के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण की कमी (माध्य = 4.32, मानक विचलन = 0.68) सर्वाधिक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। इसका निम्न मानक विचलन यह दर्शाता है कि इस समस्या के संबंध में उत्तरदाताओं के विचारों में पर्याप्त समानता पाई गई है, अर्थात् अधिकांश उत्तरदाता इस समस्या को समान रूप से गंभीर मानते हैं।

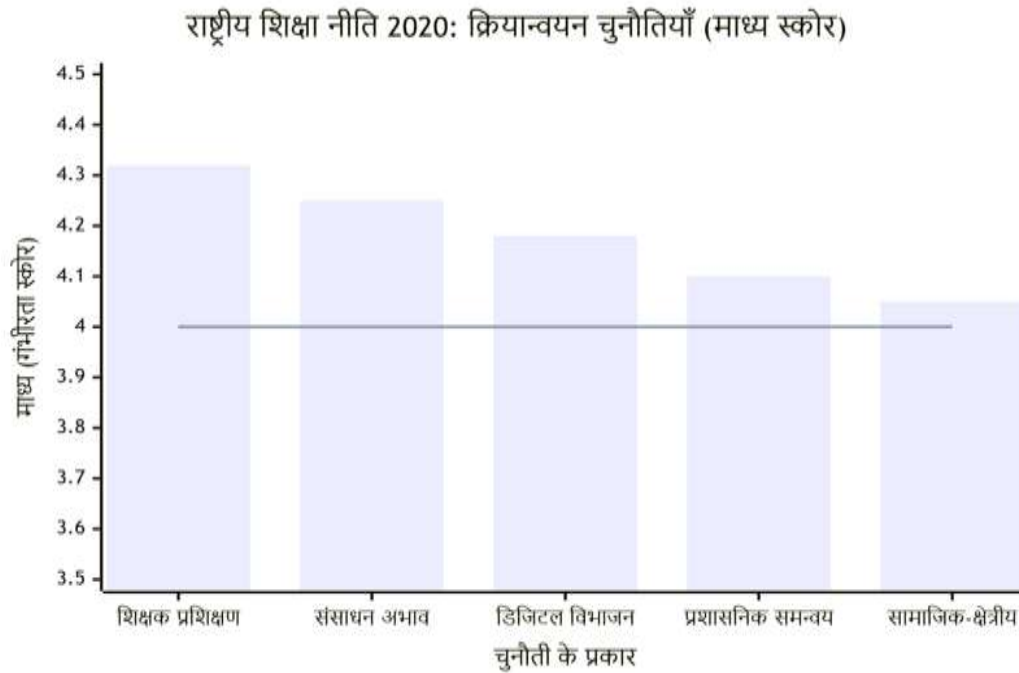
इसके पश्चात संसाधनों का अभाव (माध्य = 4.25, मानक विचलन = 0.72) तथा डिजिटल विभाजन (माध्य = 4.18, मानक विचलन = 0.75) भी प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन दोनों के मानक विचलन अपेक्षाकृत मध्यम स्तर के हैं, जो यह संकेत करते हैं कि उत्तरदाताओं के विचारों में आंशिक भिन्नता होते हुए भी समग्र रूप से सहमति विद्यमान है।

प्रशासनिक समन्वय की कमी (माध्य = 4.10, मानक विचलन = 0.80) भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में परिलक्षित होती है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक मानक विचलन यह दर्शाता है कि इस विषय पर उत्तरदाताओं के विचारों में कुछ विविधता पाई जाती है।

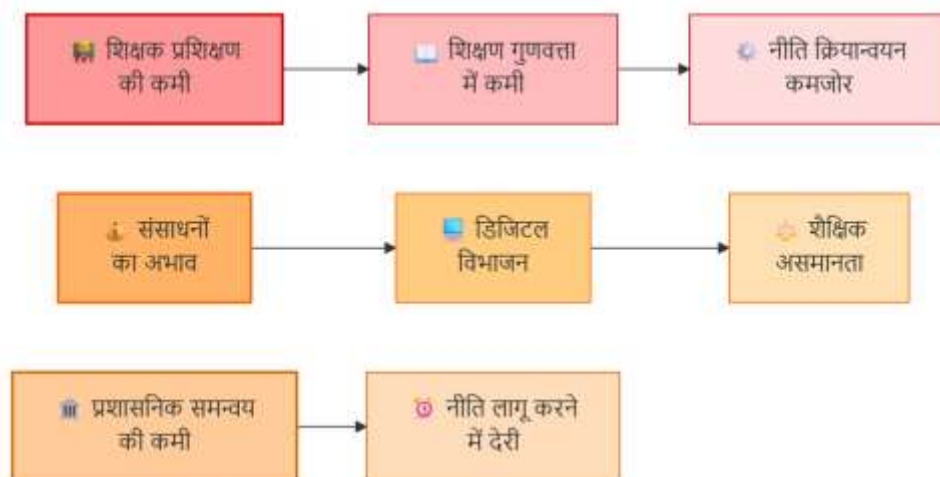
अंततः सामाजिक-क्षेत्रीय असमानता (माध्य = 4.05, मानक विचलन = 0.84) का मानक विचलन सर्वाधिक पाया गया है, जो यह इंगित करता है कि इस समस्या के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में अधिक भिन्नता है। यद्यपि इसका माध्य अन्य चुनौतियों की तुलना में थोड़ा कम है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है।

अतः समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता एवं डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियाँ प्रमुख बाधा के रूप

में विद्यमान हैं, जिनके समाधान हेतु विशेष नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।



चित्र 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण



चित्र 3: प्रमुख चुनौतियों के पारस्परिक संबंध एवं प्रभाव

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन अपने उद्देश्यों एवं प्रावधानों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी होने के बावजूद अनेक व्यावहारिक चुनौतियों से प्रभावित है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों एवं उनके विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों का अभाव, डिजिटल विभाजन, प्रशासनिक समन्वय की कमी तथा सामाजिक-क्षेत्रीय असमानताएँ प्रमुख बाधाओं के रूप में विद्यमान हैं।

विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण की कमी को सर्वाधिक गंभीर चुनौती के रूप में पाया गया, जो यह दर्शाता है कि नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की दक्षता एवं अभिमुखीकरण को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संसाधनों की अपर्याप्तता एवं तकनीकी असमानता भी शिक्षा की गुणवत्ता एवं समान अवसरों को प्रभावित करती

है, जिससे नीति के समावेशी स्वरूप को पूर्णतः प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

अध्ययन यह भी संकेत करता है कि प्रशासनिक स्तर पर समुचित समन्वय एवं स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण क्रियान्वयन की प्रक्रिया में असंगति उत्पन्न होती है। साथ ही सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ शिक्षा के अवसरों में अंतर उत्पन्न करती हैं, जो नीति के उद्देश्यों के विपरीत है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता केवल उसके सैद्धांतिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी, समन्वित एवं संसाधन-संपन्न क्रियान्वयन पर आधारित है। यदि पहचानी गई चुनौतियों का समयबद्ध एवं योजनाबद्ध समाधान किया जाए, तो यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम सिद्ध हो सकती है।

7. सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बहुआयामी एवं व्यावहारिक उपायों को अपनाना आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

प्रथम, शिक्षकों के लिए निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे वे नवीन शिक्षण विधियों, डिजिटल उपकरणों एवं नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से समझकर कक्षा-कक्ष में लागू कर सकें।

द्वितीय, विद्यालयों में शैक्षिक एवं डिजिटल संसाधनों का समुचित विस्तार किया जाना आवश्यक है, जिसमें स्मार्ट कक्षाएँ, इंटरनेट सुविधा, ई-लर्निंग

सामग्री तथा तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके।

तृतीय, प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश, प्रभावी समन्वय एवं निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिससे नीति के प्रावधानों का समयबद्ध एवं एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

चतुर्थ, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं एवं अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके तथा शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

पंचम, नीति के प्रति सभी हितधारकों—शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी एवं प्रशासन—के मध्य जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे नीति के उद्देश्यों की स्पष्ट समझ विकसित हो सके।

षष्ठ, वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे आवश्यक संसाधनों का समुचित वितरण हो सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं भविष्य उन्मुख बनाया जा सकेगा।

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। नई दिल्ली: भारत सरकार।

कुमार, ए. (2022)। भारतीय शिक्षा प्रणाली में नीतिगत सुधार एवं चुनौतियाँ। भारतीय शिक्षा समीक्षा, 10(2), 34–48।

शर्मा, आर. (2023)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 12(2), 45–60।

गुप्ता, एस. (2024)। डिजिटल शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति: अवसर और चुनौतियाँ। शिक्षा एवं विकास जर्नल, 15(1), 78–92।

वर्मा, पी. (2022)। शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव। शिक्षक शिक्षा पत्रिका, 8(1), 21–35।

सिंह, डी. (2023)। शिक्षा में तकनीकी समावेशन: वर्तमान परिदृश्य एवं समस्याएँ। समकालीन शिक्षा अध्ययन, 9(3), 56–70।

तिवारी, एम. (2021)। ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा में असमानताएँ: एक तुलनात्मक अध्ययन। शिक्षा शोध पत्रिका, 7(2), 88–102।

मिश्रा, एन. (2024)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ। भारतीय शैक्षिक नीति जर्नल, 14(1), 63–79।

चौधरी, वी. (2023)। डिजिटल विभाजन एवं शिक्षा पर उसका प्रभाव। शिक्षा एवं समाज, 11(2), 40–55।

जैन, के. (2022)। विद्यालयी प्रशासन एवं नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ। शैक्षिक प्रबंधन पत्रिका, 6(1), 15–29।

यादव, एस. (2023)। समावेशी शिक्षा एवं सामाजिक समानता के आयाम। शिक्षा दृष्टि, 13(2), 72–86।

अग्रवाल, आर. (2024)। नई शिक्षा नीति और भविष्य की शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा विमर्श, 16(1), 90–105।